from pillar to post and yet do not get a seat, those who get into the chance list bribe the officials and manage to travel by the same plane. This has become an everyday affair. Apart from that, it has also become an everyday practice on the part of the officials to take bribe by threatening the passengers who have duly paid customs duty. An instance in point is of Shri Selvaraj who was coming from Dubai to see his mother who was critically ill. In spite of the fact that he had got his ticket okayed, he could not get a seat in the plane. Another case is of a lady who was coming from Muscat for her own marriage. She could not reach her native place in time even after greasing the palm of the officials. Yet another case is of one Mr. Shamsudin who was deprived of Rs. 240/- by a customs official in spite of the fact that he had paid all dues by way of customs duty. These cases have been reported in the Malayala Manorama daily of 5th June, 1980. About 50 such people who were subjected to such fraud, reached Kerala by a special bus and reported the matter to the above-mentioned daily. Even after complaints were raised in the past about such fraudulent practices, the people involved in the fraud are freely operating without any fear. This causes apprehension and dismay to the people. The Central Government and the Civil Aviation authorities should pay immediate attention to this problem. The corruption and the fraud that is being practised there will besmirch the fair name of our country. Therefore quick and stern action should be taken against such corrupt officials.

(v) MEASURES TO STOP EXPLOITATION OF JUTE GROWERS

श्री कुमर लाल बैठा (अररिया): अध्यक्ष महोदय, बिहार में जूट उत्पादकों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई है । जूट, जिस से देश की जूट मिलें ही नहीं चलतीं, देश के बाहर भी यह निर्यात किया जाता है, जिससे देश को दुर्लभ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, किन्तु इस की कीमत और खरीददारी में घोर अनियमितता बरती जाती है । खरीद की जो कीमत तय की जाती है, वह जूट के उत्पादन खर्च से भी कम है । भारतीय जूट निगम ने जूट की अनेक श्रेणियां निर्धारित की हैं और उस आधार पर खरीद के लिए जो कीमतें निर्धारित की जाती हैं, वे अत्यन्त भ्रामक हैं और भ्रष्टाचार के स्रोत हैं, जिस से जूट निगम द्वारा किसानों से जूट खरीदते समय उस का भयंकर शोषण होता है । इधर हाल में जूट निगम ने अपने क्रय केन्द्रों को भी बन्द कर दिया है जहां चाहिए यह था कि इन केन्द्रों को ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाये और ग्रामीण जूट उत्पादकों से गांव में ही जूट खरीद कर उन्हें शोषण से बचाया जाये । इस के बदले खरीद केन्द्रों को भी बन्द कर किसानों को भयंकर कठिनाई में डाल दिया गया है ।

जूट उत्पादक निजी खरीददारों द्वारा मनमानी कीमत में जूट खरीद का शिकार हो रहे हैं । उन्हें उत्पादन से कम खर्च पर जूट बेचना पड़ रहा है, जिस से धीरे-धीरे वे जूट का उत्पादन छोड़ते भी जा रहे हैं । यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति होगी ।

अतः सरकार से आग्रह है कि बोआई के ठीक पूर्व कृषि मंत्रालय जूट की खरीद का उचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे और न्यूनतम मूल्य से नीची बाजार दर होने पर जूट निगम को बाजार से सीधी खरीद का आदेश दे ।

जूट निगम की क्रय शाखा को ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाये ।

जूट की श्रेणियों को कम किया जाये, जिस से जूट उत्पादक ठगी एवं शोषण के शिकार न हों ।

अभी तक बिहार क्षेत्र का जोन्ल कार्यालय बिहार से बाहर है और उस के पदाधिकारी भी गैर-हिन्दी क्षेत्र के हैं, जिस से किसानों को अपनी शिकायतों और कठिनाइयों को इन अधिकारियों तक पहुंचाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अतः इस कार्यालय को बिहार में ही स्थापित किया जाये और हिन्दी जानकार पदाधिकारियों की वहां पर पदस्थापना की जाये ।

[श्री डूमर लाल बैठा]

इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक स्थानों फारबिसगंज, किसनगंज, मुरलीगंज में प्रस्तावित जूट मिलों का शीघ्र निर्माण कर प्रान्त भर की जूट खपत की व्यवस्था का स्थायी हल निकाले ।

प्रश्न अत्यन्त लोक महत्व का है ।

(vi) NEED TO PROVIDE DIESEL TO FARMERS OF THE DROUGHT AFFECTED AREAS OF MADHYA PRADESH FOR SOWING KHARIF CROP

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा): मैं केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी का ध्यान प्रदेश में व्याप्त डीजल की भारी कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इस समय मध्य प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल हेतु पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं मिल पा रहा है, जिस के कारण कृषक वर्ग परेशान है एवं राज्य में यह समस्या चिन्ता का विषय बना हुआ है । जैसा कि ज्ञात है कि पिछले वर्ष प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा था, जिस के कारण खरीफ एवं रबी दोनों फसलें चोपट हो गई थीं। परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि आने वाली खरीफ फसल के लिये कृषि कार्य सुचारु रूप से चले, किसानों को अविलम्ब पर्याप्त मात्रा में डीजल मिलने की व्यवस्था की जाये एवं वर्षा के मौसम को ध्यान में रखते हुए 300 से 400 लीटर डीजल प्रति ट्रेक्टर अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाये क्योंकि 10-15 दिन बाद ज्यादातर ग्रामीण रास्ते कम से कम दो माह के लिये बन्द हो जावेंगें और समय पर डीजल न मिलने से किसानों को भारी नुकसान होगा।

13 hrs.

(vii) NEED FOR INQUIRY INTO THE ALLEGED SHADY DEALS OF OFFICIALS OF FOOD CORPORATION OF INDIA AT MANCHERIAL IN ANDHRA PRADESH

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad): Mr. Speaker, Sir recently, the Food Corporation of India godown at Mancherial in Andhra Pradesh has sold more than 200 quintals of rice at Rs. 6/- per quintal inclusive of gunny bag while the price of the gunny bak itself is more than Rs. 7/- by declaring the said rice as rotten and unfit for human consumption. In the same manner some days back sugar was also declared as spoiled and sold at Rs. 120/- per quintal while the market rate was Rs. 600/- per quintal. These sales are taking place secretly. I am sure there is a big racket where some FCI officers and some merchants have come to certain understanding and disposing off rice and sugar at a throw-away price and making huge profits at the cost of public fund. I would request the Minister for Agriculture to appoint an independent officer and get the whole thing enquired and let this House know, during the last one year how many quintals of rice and sugar were declared unfit for human consumption and at what price these were disposed off and what is the procedure followed in disposing.

MR SPEAKER: Before we adjourn for lunch, I would like to announce that after lunch, the first item will be papers to be laid on the Table and the next, the reply by the Railway Minister to the discussions on the Railway Budget.

1302 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen past of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair*]

MR. CHAIRMAN: Shri Maganbhai Barot.